

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-02

देहरादून : दिनांक 06 जून 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) बाढ़ सुरक्षा (लघु निर्माण) मद के अन्तर्गत योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-727/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/पी-27(एस0सी0एस0पी0), दिनांक 07.02.2023 में किये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति उपयोजना (एस0सी0एस0पी0) बाढ़ सुरक्षा (लघु निर्माण) मद के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड कालसी के ग्राम पंचायत सराड़ी के फरियाना खेडा स्थित कृषि भूमि की सराड़ी खड्ड से बाढ़ सुरक्षा योजना (घोषणा संख्या-665/2021) की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल धनराशि रू0 16.23 लाख (रू0 सोलह लाख तैंईस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में इतनी ही धनराशि की निम्न विवरणानुसार व्यय हेतु अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. योजना से ग्राम पंचायत सराड़ी के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के घरों तथा भूमि को ही बाढ़ सुरक्षा प्रदान करने हेतु बनाया जाय।
2. सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कहीं आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत न हो। अन्य योजना/विभाग से वित्त पोषित/स्वीकृत होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि समर्पित की जाय।
5. योजना से मात्र अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही लाभान्वित होंगे। योजना प्रारम्भ किये जाने से पूर्व यह भलीभांति जांच कर ली जाय कि क्या पूर्व में उक्त लाभार्थियों को लाभान्वित तो नहीं किया गया है।
6. उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना (नियोजन, धनावंटन तथा उपयोग) अधिनियम, 2013 का पालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाय।
7. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
8. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें।
9. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
10. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
11. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। 1

- संलग्नक- Allotment ID**

